

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Tuesday, 27th August , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 06 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 'साक्षरता', 'पूर्ण साक्षरता' को परिभाषित किया
Page 07 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	स्पेसएक्स जोखिम भरे निजी स्पेसवॉक में नई तकनीक का परीक्षण करेगा
Page 11 Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	डॉक्टर के दफ़्तर में दिखने वाले कुछ सरल चिकित्सा उपकरणों के पीछे की कार्यप्रणाली
Page 13 Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था	रेलवे की नज़र परमाणु ऊर्जा पर है
समाचार में टर्म	एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय	अपराध, स्वास्थ्य-कर्मी सुरक्षा और आत्म-परीक्षण
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक



Page 06: Prelims Facts

भारत सरकार ने साक्षरता को पुनः परिभाषित किया है, जिसमें पढ़ना, लिखना, गणना करना और महत्वपूर्ण जीवन कौशल शामिल हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) का लक्ष्य सालाना एक करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है।

⇒ प्रगति के बावजूद, साक्षरता संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, 25.76 करोड़ लोग निरक्षर हैं, जो निरंतर प्रयासों और वित्तपोषण की आवश्यकता को उजागर करता है।

Education Ministry defines 'literacy', 'full literacy' in push for adult literacy

Maitri Porecha

NEW DELHI

In a letter to all States, the Education Ministry has defined 'literacy', and what it means to achieve 'full literacy,' in light of a renewed push for adult literacy under the New India Literacy Programme (NILP), a fiveyear programme (2022-27) that aims to onboard one crore learners aged above 15 every year across all States and Union Territories.

Union School Education Secretary Sanjay Kumar, in the letter, has stated that literacy may be understood as the ability to read, write, and compute with comprehension, that is to identify, understand, interpret and create along with critical life skills such as digital and financial literacy. Full literacy (to be considered equivalent to 100%



New India Literacy Programme (NILP) aims to onboard 1 crore learners per year. GETTY IMAGES

literacy) will be achieving 95% literacy in a State or Union Territory.

Mr. Kumar further writes that a non-literate person may be considered as literate under the NILP, as per the aforementioned definition when he/she has been declared literate after taking the Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test (FLNAT).

According to data ac-

cessed by *The Hindu*, in 2023, 39,94,563 adult learners appeared for FLNAT in March and September, out of which 36,17,303 were certified 'literate'.

In 2024, FLNAT was conducted on March 17, in which 34,62,289 learners appeared.

However, only 29,52,385 (85.27%) were certified as literate. While the pass percentage in FLNAT hovered between 89.64% and 91.27% in 2023, in 2024 it has dropped lower to 85.27%.

In 2024-25, the Ministry has allocated a budget of ₹160 crore for NILP. According to the latest Union Budget document, only ₹76.41 crore was actually utilised towards the scheme in 2022-23.

In 2023-24, the allocation was hiked to ₹157 crore, but later brought down to ₹100 crore in the

revised estimates of the Union Budget.

Significant challenge

According to the 2011 Census, India faces a significant literacy challenge with 25.76 crore non-literate individuals in the age group of 15 years and above, comprising 9.08 crore males and 16.68 crore females.

Despite the progress made under the Saakshar Bharat programme, which certified 7.64 crore individuals as literate between 2009-10 and 2017-18, an estimated 18.12 crore adults in India remain non-literate. The letter savs non-literate individuals face disadvantages in various aspects of life such as financial transactions, job applications, understanding of rights and participation in higher productivity sectors.

साक्षरता की नई परिभाषा



THE MORE HINDU Daily News Analysis

 सरकार साक्षरता को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सहित समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करती है।

पूर्ण साक्षरता तब प्राप्त होती है जब कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 95% साक्षरता तक पहुँच जाता है।

 यदि कोई व्यक्ति मुलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मुल्यांकन परीक्षण (FLNAT) पास करता है तो उसे NILP के तहत साक्षर माना जाता है।

मुलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मुल्यांकन परीक्षण (FLNAT):

- 🔖 FLNAT पंजीकृत गैर-साक्षर शिक्षार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए भारत में आयोजित एक राष्ट्रव्यापी मुल्यांकन है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है।
- योग्यता प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में उनकी उपलब्धि को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।

भारत में साक्षरता पर सांख्यिकीय डेटा

- 2011 की जनगणना: भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 25.76 करोड निरक्षर व्यक्ति थे, जिनमें 9.08 करोड पुरुष और 16.68 करोड महिलाएँ थीं।
- 🗪 साक्षर भारत: 2009-10 और 2017-18 के बीच 7.64 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया।
- 2023 FLNAT: 39,94,563 वयस्क शिक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 36,17,303 साक्षर के रूप में प्रमाणित हुए।
 2024 FLNAT: 34,62,289 शिक्षार्थी उपस्थित हुए, और 29,52,385 (85.27%) प्रमाणित हुए, जो 2023 में 89.64% से घटकर ९१.२७% हो गया।

UPSC Prelims PYQ: 2018

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने की आवश्यकता होगी।
- 2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
- 3. भारत में, 90% से अधिक शिक्षक-5 शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: b)



Page 07 : Prelims Fact

स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन पहला निजी स्पेसवॉक होगा, जिसमें स्लिम स्पेससूट और बिना एयरलॉक वाला संशोधित क्रू ड़ैगन जैसी नई तकनीक शामिल होगी।

 मंगलवार को लॉन्च होने वाला यह मिशन 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने, उच्च विकिरण वाले वातावरण में उपकरणों का परीक्षण करने और निजी अंतरिक्ष उडान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

स्पेसएक्स मिशन के बारे में अधिक जानकारी:

- स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन अभिनव स्पेसवॉक तकनीक पेश करता है।
- इसमें नए स्लिम स्पेससूट और संशोधित क्रू डैगन वाहन शामिल है जो अपने हैच डोर को सीधे अंतरिक्ष में खोलने में सक्षम है, जिससे एयरलॉक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- एक अरबपति, एक सेवानिवृत्त लड़ाकू पायलट और दो स्पेसएक्स इंजीनियरों को लॉन्च करने वाले इस मिशन का लक्ष्य आईएसएस से कहीं आगे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचना है।
- क्रू डैगन और स्पेससूट का परीक्षण वैन एलन बेल्ट में उच्च विकिरण वाले वातावरण में किया जाएगा।





SpaceX to test new tech in risky private spacewalk

SpaceX's attempt at the first-ever private spacewalk will be a test of trailblazing equipment, including slim spacesuits and a cabin with no airlock, in one of the riskiest missions yet for Elon Musk's space

riskiest missions yet for Elon Musk's space company. A billionaire entrepreneur, a retire military fighter pitot, and two SpaceX employees are poised to launch on Tuesday abord at modified Grew Dragon craft, before embarking on a 20-minute spacewalk 700 km into space two days later. In one, walking into the empty expanse of space has only been attempted by government aeronauts on the

SpaceX's five-day mission, dubbed Polaris Dawn', will swing in an elliptical orbit, and will go the farthest from earth any humans will have ventured since the end of NASA's Apollo programme

International Space Station (ISS), 400 km up.

SpaceX's five-day mission, dubbed
Polaris Dawn', will swing in an elliptical
orbit, passing ac close to the earth as 190 km and as far as 1,400 km, the fairthest of the control of NaSA's Apollo programme in 1972.
Retired NASA astronaut Garrett
Resiman said in an interview that the crew is going to "a much higher altitude, with a more severe radiation environment than we have been to since Apollo."
Crew members will don SpaceX's new spacesuits in a Crew Dragon vehicle modified to open its hatch door in so that removes the need for an alrock.
The mission has been bankrolled by Jared Issacman, the founder of electronic stations of the control o

Crew Dragon's adout 45 nours in advance. Crew Dragon's cabin will be depressurised and exposed to the vacuum of space. While only two of the astronauts will float outside, tethered by an oxygan line, the whole crew will depend on their spacesuits for life support. Days before the spacewall, the support. Days before the spacewall, cate of the space of the

missions like Polaris.
SpaceN officials and the Polaris crew
said during a Monday news conference
they have planned for an array of
contingency scenarios if something
during the mission goes wrong, such as
an oxygen leak or failure to reseal the
hatch door, but they didn't detail what
those were.



UPSC Prelims PYQ: 2018

प्रश्न: भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. पी.एस.एल.वी. पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं जबकि जी.एस.एल.वी. मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- 2. पी.एस.एल.वी. द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं।
- 3. जी.एस.एल.वी. एम.के. III एक चार-चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है, तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 2
- (d) केवल 3

उत्तर: a)





Page: 11: GS 3: Science & Technology

यह लेख बताता है कि थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, तराजू और स्फिग्मोमैनोमीटर जैसे सामान्य चिकित्सा उपकरण वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करते हैं, और सटीक माप के लिए स्वास्थ्य देखभाल में उनके तंत्र का विवरण देता है।



The working behind some simple medical tools one sees in a doctor's office

How do thermometers, stethoscopes, weighing scales, and sphygmomanometers work? A sphygmomanometer is a device that monitors blood pressure. The manual version consists of an inflatable cuff and a manometer, the part that measures pressure

hen you visit your doctor for a consultation, they need to get a sense of how well your body is. Thanks to the thermometer, the stethoscope, the weighing scale, and the sphygmomanometer, you only need a few minutes to acquire this data.

What is a thermometer?

A thermometer is a device to measure the A thermometer is a device to measure the temperature of an object. Every thermometer has a part that is sensitive to changes in temperature and another that shows these changes as numbers. In the once-ubiquitous mercury

thermometer, a small amount of mercury in a glass bulb is the temperature sensor. It a glass built is the temperature sensor. Its rise and fall in response to temperature changes happens in a glass capillary marked with numerical values. When the mercury bulb is brought in contact with a warmer object, the liquid contact with a warmer object, the liquid expands and rises up through the capillary. The number next to its level is the object's temperature.

This relationship between the temperature and the mercury's level

temperature and the mercury's level requires mercury thermometers to be carefully calibrated such that the capillary's width, the mercury's temperature, and the markings on the scale match each other. It's also important that the volume of the material in the bulb varies linearly by the temperature.

That is, if it expands by 1 unit for every 1°C change in temperature, it should do so by 10 units for a 10°C change.

Researchers have developed thermometers today that use digital

components to infer the temperature. For example, thermal guns of the sort used to check the temperatures of people entering malls and supermarkets during the COVID-19 pandemic contains a detector that interprets the radiant power of a warm body as changes in the voltage or resistance in a circuit, and uses that to

produce a temperature readout.

Another common type of thermometer is the thermistor: a semiconductor whose resistance is sensitive to changes in temperature. Thermistor-based thermometers have become a common sight in clinics and hospitals.

What is a stethoscope?

The stethoscope consists of a diaphragm at one end and an earpiece at the other, at one end and an earpiece at the other, with a tube connecting the two. When the diaphragm is placed against the skin, sounds inside the body near that area cause the diaphragm to vibrate, creating pressure waves in the air filling the tube that are transmitted via the earpiece to a

The piece that holds the diaphragm has a bell-shaped opposite side. The diaphragm is better to pick up high-frequency sounds while the bell is

suited for low-frequency ones.
Stethoscopes also have electronic
versions with additional features. A
particularly important one is sound
amplification, to help the listener interpret sounds too faint to hear in an

acoustic stethoscope.
Some companies have developed stethoscopes that can collect sound data, analyse it for signs of certain heart conditions, and transmit the results wirelessly to a smartphone.

How do weighing scales work?

Perhaps the simplest of (today's) weighing scales where some significance is the spring scale, a common sight in clinics, houses, and grocery stores. The centrepiece of this device is a spring. When the spring is placed under a plate and an object is placed on top of the plate and an object is placed on top of the plate, the device is calibrated to measure the force exerted by the object based on how much the spring is compressed. Alternatively, the spring can be attached to a hook at the bottom from which an object can be suspended. The object's force is calculated based on how much

The operator needs to make sure the spring works as expected at regular intervals and to calibrate the weighing scale at the location where it's going to be used, rather than somewhere else, to account for local variations in gravity. An analog weighing scale translates the

spring's deformation to a weight measure by a straightforward calibration. An electronic weighing scale uses a force transducer instead. Two common ones are load cells and strain gauges. A load cell is a circuit that, when a voltage is applied, transmits different amounts of current depending on the weight acting on it. A strain gauge is a conductor whose resistance changes depending on its

What is a sphygmomanometer? A sphygmomanometer is a device that

was programment is a tweeter that monitors blood pressure. The manual version consists of an inflatable cuff and a manometer, the part that measures pressure. The cuff is strapped around an individual's arm, at roughly the same height as the heart. The pressure inside

the cuff is increased by pumping a bladder of air. The doctor or nurse keeps bladder of air. The doctor of nurse keeps track of the cuff pressure by its link to the manometer, which measures pressure as the level of mercury in a capillary (like in a mercury thermometer). The worker also places a stethoscope over the brachial artery, the main artery bringing blood to

when the pressure in the cuff reaches a suitably high value, the artery will be pinched off and blood flow will stop. The orker then slowly releases the pressure worker then slowly releases the pressure in the cuff. When the pressure in the artery drops enough to allow blood to flow, a whooshing sound is heard via the stethoscope. The manometer reading at this point is the systolic pressure. When the planching systolic pressure. the whooshing sound stops altogether, the manometer reading is the diastolic pressure. The whooshing is called the Korotkov sound, for the physician Niko Korotkov, who discovered it in 1905.

Electronic sphygmomanometers automate this process with a slight difference. When the pressure in the cuff is neither too high to stop blood flow nor too low to let it flow unimpeded, and partly restricts flow, the cuff pressure will oscillate over a small range in sync with the expansion and contraction of the artery. The device uses this oscillation to calculate blood pressure. Electronic sphygmomanometers

require less skill to operate but they are also less accurate than the mechanical, mercury-based version, which are preferred during clinical trials. In particular, electronic devices may no provide accurate readouts when the individual has a pulse-related abnormality such as pulsus paradoxus or arrhythmia



THE DOWN HINDU Daily News Analysis

डॉक्टर के निदान में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची

यहां दी गई है:

	समारोह	विवरण और कार्य सिद्धांत
थर्मामीटर	शरीर का तापमान मापता है।	 पारा थर्मामीटर: इसमें पारा से भरा बल्ब और संख्यात्मक चिह्नों वाली कांच की केशिका होती है। तापमान में परिवर्तन के कारण पारा फैलता या सिकुड़ता है, जो तापमान को इंगित करने के लिए केशिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। डिजिटल थर्मामीटर: तापमान में परिवर्तन का पता लगाने के लिए इन्फ्रारेड या थर्मिस्टर जैसे सेंसर का उपयोग करता है, जिन्हें फिर डिजिटल रीडिंग में बदल दिया जाता है।
स्टेथोस्कोप	शरीर की आंतरिक आवाज़ें सुनता है।	 ध्विनक स्टेथोस्कोपः इसमें उच्च आवृत्ति वाली ध्विनयों के लिए एक डायाफ्राम और कम आवृत्ति वाली ध्विनयों के लिए एक घंटी होती है, जो एक ट्यूब द्वारा इयरपीस से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप (स्टेथोफोन)ः शरीर की ध्विनयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बढ़ाता है और इसमें रिकॉर्डिंग क्षमताए और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसे अतिरिक्त निदान शामिल हो सकते हैं। ये डिवाइस स्मार्टफ़ोन या अन्य डिवाइस को ध्विन डेटा संचारित करते हैं।
वजन मापने का पैमाना	शरीर का वज़न मापता है।	 स्प्रिंग स्केल: प्लेट के नीचे स्प्रिंग का उपयोग करता है; वजन को स्प्रिंग के संपीड़न या विस्तार की डिग्री से मापा जाता है। स्थानीय गुरुत्वाकर्षण भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए अंशांकन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्केल: लोड सेल या स्ट्रेन गेज का उपयोग करके वजन के



THE MER HINDU

Daily News Analysis

		यांत्रिक बल को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिसे डिजिटल स्क्रीन पर वजन रीडिंग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
स्फिग्मोमैनोमीटर	रक्तचाप मापता है।	 मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर: इसमें एक इन्फ्लेटेबल कफ शामिल है, जो पारा या एनरॉइड मैनोमीटर से जुड़ा हुआ है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव निर्धारित करने के लिए रक्त प्रवाह ध्वनियों (कोरोटकोव ध्वनियों) का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमैनोमीटर: धमनी रक्त प्रवाह के कारण होने वाले दबाव दोलनों को महसूस करने के लिए ऑसिलोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे रक्तचाप माप स्वचालित हो जाता है। घर पर उपयोग के लिए आसान है, लेकिन कुछ हृदय संबंधी स्थितियों वाले रोगियों में सटीकता के मुद्दे हो सकते हैं।

UPSC Prelims PYQ: 2019

प्रश्न: पहनने योग्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, पहनने योग्य उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूरा किया जाता है?

- 1. किसी व्यक्ति की स्थान पहचान
- 2. किसी व्यक्ति की नींद की निगरानी
- 3. श्रवण बाधित व्यक्ति की सहायता करना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3



उत्तर: d)

Page 13: GS 3: Indian Economy: Infrastructure - Railways

भारतीय रेलवे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा सहित परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज की जा रही है।

इसका लक्ष्य 30,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना है, परिचालन लागत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी करना है।

खबर के बारे में:

- भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है और 2029-30 तक 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है।
- रेलवे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा के साथ-साथ कैप्टिव परमाणु ऊर्जा के उपयोग की खोज कर रही है।
- रेलवे परिचालन लागत को कम करने के लिए छोटे रिएक्टरों सिहत अपनी स्वयं की कैप्टिव बिजली उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
- रेलवे ट्रेनों और इसकी सुविधाओं के लिए बिजली पर सालाना लगभग ₹20,000 करोड़ खर्च करता है।
- 2023 में, रेलवे ने 147 मेगावाट सौर ऊर्जा और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा चालू की, साथ ही
 2,150 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता सुरक्षित की।

भारतीय रेलवे में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना संभावनाएँ:

- पर्याप्त क्षमता: भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2029-30 तक 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को तैनात करना है, जिसमें सौर, पवन और जल विद्युत शामिल हैं।
- पर्यावरणीय प्रभाव: नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान देगा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढाएगा।
- ऊर्जा स्वतंत्रता: कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयों में निवेश करके, रेलवे अधिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर सकता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है।
- तकनीकी उन्नति: नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में उन्नति और घटती लागत सौर और पवन ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाना अधिक व्यवहार्य बनाती है।
- परमाणु ऊर्जा: यह एक विश्वसनीय, कम कार्बन ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है, जो महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी लाने और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय एकीकरण का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ:

- प्रारंभिक निवेश: नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और कैप्टिव बिजली इकाइयों की स्थापना के लिए उच्च अग्रिम लागत एक वित्तीय बोझ हो सकती है
- अंतराल: सौर और पवन ऊर्जा आंतरायिक स्रोत हैं, जिन्हें निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है।

Railways eyes nuclear energy



Power guzzler: Railways, the largest power consumer, spends ₹20,000 cr. a year to run trains, establishments. AFP

Abhishek Law

NEW DELHI

The Indian Railways is exploring the possibility of using captive nuclear power as it seeks to cut fossil fuel use and step up renewable resources.

The Railways aims at achieving Net Zero carbon emissions by 2030. To reach this goal, it estimates requiring 30,000 MW of renewable energy capacity by 2029-30.

Apart from nuclear power, the Railways is already in the process of commissioning solar and wind-based power units. Hydel power would also be tapped. In all cases, the public sector behemoth would look at having captive power generating units.

Senior officials told *businessline* discussions would be taken up with the Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) shortly. For renewable power, the Railways is exploring partnerships with Solar Energy Corporation of India (SECI), NTPC, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), among others.

"In each case, we will look to have our own captive use power plants, small reactors, captive power generating units and so on. Work is going on on the revenue model, or purchase pact. Obviously, we will look at a lower cost model so that operating costs come down," the official said.

"The Railways plans to procure renewable energy via different power procurement modes for its energy requirements," the official said.

The Railways is the largest consumer of electricity and spends close to ₹20,000 crore annually to run trains and its establishments.

In 2023, about 147 MW solar plants and about 103 MW wind units were commissioned, with another 2,150 MW renewable capacity tied up. (The writer is with The Hindu businessline)



THE DOWN HINDU Daily News Analysis

- बुनियादी ढांचे का विकास: मौजूदा प्रणालियों में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए नए बुनियादी ढांचे और उन्नयन की आवश्यकता जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।
- नियामक बाधाएं: नियामक ढांचे को नेविगेट करना और नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना कार्यान्वयन में देरी कर सकता है।
- रखरखाव और पिरचालन लागत: नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के प्रबंधन और रखरखाव, जिसमें प्रौद्योगिकी विश्वसनीयता के साथ संभावित मुद्दे शामिल हैं, के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।

UPSC Mains PYQ: 2014

प्रश्न: किराए को विनियमित करने के लिए रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना से नकदी की कमी से जूझ रही भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को संचालित करने के दायित्व के लिए सब्सिडी की मांग करनी पड़ेगी। बिजली क्षेत्र के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, चर्चा करें कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या निजी कंटेनर ऑपरेटरों को लाभ होने की उम्मीद है।





Term In News: Unified Lending Interface

रिजर्व बैंक घर्षण रहित ऋण के लिए एक एप्लीकेशन का परीक्षण कर रहा है - यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI)। इसे जल्द ही पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा और यह ऋण के मामले में UPI बन जाएगा।

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI)

पृष्ठभूमि

o अगस्त 2023 में, RBI ने एक सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे ऋण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य लागत कम करना, संवितरण में तेज़ी लाना और मापनीयता को बढाना है।

- o हाल ही में, RBI गवर्नर ने इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) रखने का प्रस्ताव रखा।
- o उन्होंने कहा कि जिस तरह UPI ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है, उसी तरह ULI से भी भारत में ऋण परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है।



▶ ULI की आवश्यकता

- o भारत के तेज़ डिजिटलीकरण ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे बैंकों, NBFC, फिनटेक कंपनियों और स्टार्ट-अप द्वारा भुगतान, ऋण और वित्तीय सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा मिला है।
- o हालाँकि, ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा विभिन्न प्रणालियों में बिखरा हुआ है, जिससे सुचारू और समय पर ऋण देने में बाधाएँ पैदा हो रही हैं।

के बारे में

- o ULI कई स्रोतों से ऋणदाताओं तक राज्य भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के निर्बाध, सहमित-आधारित प्रवाह को सक्षम करेगा।
- o इससे ऋण मूल्यांकन में तेजी आएगी, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं को लाभ होगा।
- o ULI प्लेटफ़ॉर्म, अपने मानकीकृत API के साथ, तकनीकी एकीकरण को सरल बनाएगा और व्यापक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को कम करेगा, जिससे ऋण वितरण तेज़ और अधिक कुशल हो जाएगा।
- o इसे त्वरित पहुँच को सक्षम करने के लिए प्लग-एंड-प्ले दृष्टिकोण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- o ULI ऋणदाताओं के लिए विविध स्रोतों से डिजिटल पहुँच में सुधार करता है। पारिस्थितिकी तंत्र संभावित उधारकर्ताओं की सहमति पर आधारित है और डेटा गोपनीयता सुरक्षित है।

🟓 लाभ

o ULI वर्तमान में अलग-अलग प्रणालियों में रखे गए वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा तक पहुँच को डिजिटल बनाकर, विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण की बड़ी अप्राप्ति मांग को संबोधित करेगा।



THE Death HINDU Daily News Analysis

o विशेषज्ञों का दावा है कि JAM (जन धन, आधार, मोबाइल),

UPI और ULI का संयुक्त प्रभाव भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

के बारे में

- o UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी सहभागी बैंक का) में जोड़ती है।
- o यह कई बैंकिंग सुविधाओं, सहज निधि रूटिंग और मर्चेंट भुगतानों को एक ही हुड में मिलाकर ऐसा करता है।
- o दूसरे शब्दों में, UPI एक ऐसा इंटरफ़ेस है जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति एक ही विंडो में बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर कर सकता है।
- o इसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।

UPI की विशेषताएँ

- o चौबीसों घंटे और 365 दिन मोबाइल डिवाइस के ज़रिए तुरंत पैसे ट्रांसफर
- o अलग-अलग बैंक खातों तक पहुँचने के लिए एक ही मोबाइल एप्लिकेशन
- o परेशानी मुक्त लेनदेन क्योंकि ग्राहकों को कार्ड नंबर, खाता संख्या, IFSC आदि जैसे विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।

UPI के लाभ

बैंकों के लिए

- एक लेनदेन के लिए एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग;
- एक क्लिक दो कारक प्रमाणीकरण;
- अधिक सुरिक्षत और सुरिक्षत; आसान लेनदेन सक्षम करता है;
- अद्वितीय पहचानकर्ता

व्यापारियों के लिए

- 📤 आसान निधि संग्रह; इन-ऐप भुगतान (IAP)
- ग्राहक के वर्चुअल पते को संग्रहीत करने का कोई जोखिम नहीं;
- क्रेडिट/डेबिट कार्ड न रखने वाले ग्राहकों को टैप करें

🟓 ग्राहकों के लिए

- विभिन्न बैंक खातों तक पहुँचने के लिए एकल अनुप्रयोग;
- चौबीसों घंटे उपलब्धता;
- कोई भी व्यक्ति सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज कर सकता है;
- वर्चुअल आईडी का उपयोग सुरक्षित है

UPI लेनदेन: सांख्यिकी

- → भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में यूपीआई का उपयोग करके भुगतान 20,64,292.40 करोड़ रुपये मूल्य के थे।
- 🟓 जुलाई 2024 में कुल लेनदेन की संख्या 14,435.55 मिलियन थी।



Page: 08 Editorial Analysis Crime, health-worker safety and a self-examination

he year 2017 saw heated protests by resident doctors in Maharashtra, following a series of vicious attacks on medical personnel in rather quick succession – as is invariably the case with sensationalised criminal offences. Despite the magnitude of the problem, the solution was straightforward and run-of-the-mill. It meant bolstering security in public hospitals and strengthening legal instruments to bring the malefactors to rapid justice. Similar incidents came and went, with much happening during the COVID-19 pandemic. The knee jerk responses too continued. One is hard-pressed to recall any conspicuous precedents of swift justice.

There lies a deeper problem

It is the case of the grisly death of a promising resident doctor in Kolkata that has taken the country by storm and that has spurred the Supreme Court of India to take *suo moto* cognisance of the happening. However, emerging answers to the issue continue to remain reflexive and simplistic, and possibly reflect an incomplete understanding of the malady beneath. In its proceedings on August 20, the Court decreed the constitution of a national task force to work out measures to strengthen hospital safety. Improved infrastructure and closed-circuit television surveillance, a greater security presence at hospitals, and safe night transport are reportedly some areas that will receive attention.

In the same vein, the West Bengal government has announced the 'Rattierer Saathi (night companion') programme aimed at improving the safety of women working in night shifts, particularly in medical colleges and hospitals. While such initiatives are critical, they implicitly conflate this issue with archetypal health worker violence, which is initiated by disgruntled patients due to perceived poor health-care services, or women's safety at large. What lurks underneath is the much more insidious problem of corruption of criminal proportions.

Conventional answers to health worker



<u>Dr. Soham D.</u> <u>Bhaduri</u>

a public health specialist and an independent researcher

Emerging answers to the issue of health-worker safety continue to remain reflexive and simplistic, and could show an incomplete understanding of the malady beneath

violence, such as improving hospital security and newer legislation, have miserably failed in tackling the problem over the years. These include reasons such as underfunding which are no different than why our health systems continue to remain frail in general. But the extent to which corruption contributes to the overall loss of lives has been vastly under-appreciated. If emerging accounts are anything to go by, there is a strong likelihood of deep-rooted, organised corruption having contributed to the gruesome crime in question, not to SAFE mention other incidents and the SPACES steady erosion of public health services that may have hitherto gone unheeded. The fact that this concerns

an apex health-care institution in an

health system is acutely disconcerting.

already underfunded state public

WHO estimates

The World Health Organization estimates that corruption claims nearly \$455 billion annually worldwide, more than what it would cost to extend universal health coverage to all. In a good part of the developing world, corruption rather than a lack of funds is what majorly contributes to health-care crises and poor health outcomes. While often sensationalised, the discourse on medical corruption in India has largely concentrated on private losses and malfeasances, while its criminal dimensions have been largely underappreciated. Human resource-intensive health-care systems provide rapid breeding grounds for expansionary corruption, including the worst forms of sextortion, particularly in political systems where underfunding and poor oversight run rife.

In such circumstances, it is hard to conceive how much help would realistically accrue from merely improving the state of health workers' security and hospital infrastructure, even if they are somehow adequately implemented. Being painfully galvanised to the fact that medical corruption can claim the lives of health-care workers in addition to that of patients serves to indicate that the public health system and its drivers may be up for a rigorous self-examination.

Speedy delivery of justice in the Kolkata case is inarguably paramount, for nothing else said or done can ever serve as a consequential deterrent. Needless to say that we have traditionally fallen short in this respect, and the ramifications are for all to see.

The steps that are needed

But the national task force has a job that is arguably more monumental than simply recommending safety measures – which is to devise a potent road map to prevent and arrest medical corruption, particularly in the public sector. Certainly, this cannot be

approached solely by a team of medical doctors. It requires expert inputs from public health, medico-legal, and other allied competencies, besides meriting the participation and the sanction of the larger governing and administrative community. And, the strategies so devised have to look much beyond instituting yet another novel legislative tool.

Apart from reforms centering on administrative transparency, accountability, and oversight, effective whistle-blower reporting and protection mechanisms and thorough digitalisation of public management systems are crucial. The need for ombudsmanship and other instruments to minimise political intrusion and manoeuvring cannot be overstated. Inspiration may be drawn from how fellow nations such as Brazil continue to battle political corruption in medicine.

Much also remains to be done in the way of modernising the typical 'control and command' Indian public hospital, which remains steeped in anachronistic ways. While efficiency reasons for such a modernisation abound, their pressing moral and regulatory bases have glaringly presented today and can no longer be overlooked.

GS Paper 02 : सामाजिक न्याय – कमज़ोर वर्ग

(UPSC CSE (M) GS-2 : 2018) भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप एक पूर्वीपेक्षा है। समझाइए? (150 w/10m)

UPSC Mains Practice Question भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को कमजोर करने में भ्रष्टाचार की भूमिका की जांच करें, जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा की हालिया घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यापक सुधारों का सुझाव दें। (250 w /15 m)



संदर्भ :

- लेख भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को संबोधित करता है, खासकर कोलकाता में एक डॉक्टर की मौत के बाद।
- यह अस्पताल सुरक्षा पर पारंपिरक ध्यान की आलोचना करता है और सार्वजिनक स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गहन सुधारों की मांग करता है, पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देता है।

हिंसा पर प्रतिक्रिया

- पृष्ठभूमिः
- 2017 में, महाराष्ट्र में चिकित्सा कर्मियों पर कई हमलों के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया।
- तत्काल समाधानों में अस्पताल की सुरक्षा में सुधार और अपराधियों को दंडित करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करना शामिल था।
- इन प्रयासों के बावजूद, ऐसे मामलों में त्विरत न्याय शायद ही कभी देखा गया है, यहां तक कि COVID-19 महामारी के दौरान भी घटनाएं जारी रहीं।

गहरी अंतर्निहित समस्या

- कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की क्रूर मौत ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मामले का स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया है।
- हालांकि प्रतिक्रिया, जैसे कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन, अस्पताल की सुरक्षा में सुधार (जैसे, बेहतर बुनियादी ढांचे, सीसीटीवी निगरानी और चिकित्साकर्मियों के लिए रात्रि परिवहन) पर केंद्रित है, लेकिन ये उपाय गहरे मुद्दे, यानी भ्रष्टाचार को संबोधित करने में विफल रहे हैं।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने रात्रि पाली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'रैटियर साथी' कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन यह भी सामान्य स्वास्थ्य कर्मियों की हिंसा के साथ इस मुद्दे को जोड़ता प्रतीत होता है।

पारंपरिक समाधान विफल

- पारंपिरक प्रतिक्रियाएँ, जैसे कि बेहतर अस्पताल सुरक्षा और नया कानून, स्वास्थ्य किर्मियों के विरुद्ध हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रही हैं।
- वास्तविक समस्या भ्रष्टाचार में है, विशेष रूप से कम वित्तपोषित सार्वजिनक स्वास्थ्य प्रणालियों में।
- संगठित भ्रष्टाचार ने कोलकाता की घटना और इसी तरह के अन्य मामलों में योगदान दिया हो सकता है, जिसके स्वास्थ्य कर्मियों और रोगियों दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

प्रणालीगत भ्रष्टाचार

स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार पर WHO का अनुमान





▶ WHO का अनुमान है कि भ्रष्टाचार की वजह से दुनिया भर में सालाना लगभग 455 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आवश्यक राशि से अधिक है।

 विकासशील देशों में, भ्रष्टाचार, केवल धन की कमी के बजाय, स्वास्थ्य सेवा संकट और खराब परिणामों में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है।

 जबिक भारत में चिकित्सा भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा अक्सर निजी नुकसान पर केंद्रित होती है, इसके आपराधिक पहलुओं, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में, को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है।

 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार, जिसमें सेक्सटॉर्शन जैसे मुद्दे शामिल हैं, कम फंडिंग और खराब निगरानी के माहौल में पनपता है।

वर्तमान सुरक्षा उपायों की सीमाएँ

- स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा में सुधार और अस्पताल के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
- कोलकाता का मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे चिकित्सा भ्रष्टाचार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ रोगियों की मृत्यु का कारण बन सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

व्यापक सुधारों की आवश्यकता

- राष्ट्रीय टास्क फोर्स की भूमिका सुरक्षा उपायों से आगे बढ़नी चाहिए; इसे विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में चिकित्सा भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए एक रोडमैप विकसित करना चाहिए।
- इस प्रयास के लिए सार्वजिनक स्वास्थ्य और कानूनी विशेषज्ञों सिहत कई क्षेत्रों से इनपुट की आवश्यकता है, साथ ही शासन और प्रशासन से व्यापक भागीदारी भी।

आवश्यक प्रमुख सुधार

- सुधारों में स्वास्थ्य सेवा प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को बढ़ाना शामिल होना चाहिए।
- 📦 सार्वजनिक प्रबंधन प्रणालियों के डिजिटलीकरण के साथ-साथ प्रभावी व्हिसल-ब्लोअर सुरक्षा तंत्र आवश्यक हैं।
- लोकपाल जैसे साधन और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं।
- चिकित्सा में राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ब्राजील जैसे देशों से प्रेरणा ली जा सकती है।

सार्वजनिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

- 🔸 भारत के सार्वजनिक अस्पताल, जो अक्सर पुराने प्रबंधन मॉडल पर काम करते हैं, को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
- कार्यकुशलता से परे, आधुनिकीकरण के लिए नैतिक और विनियामक कारण अब महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

 अस्पताल की सुरक्षा को मज़बूत करना ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ़ हिंसा के मूल कारण को संबोधित करने के लिए यह अपर्याप्त है।



THE DOWN HINDU Daily News Analysis

➡ सार्वजिनक स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही को लिक्षत करने वाले व्यापक सुधार भारत में चिकित्सा किर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समग्र स्वास्थ्य पिरणामों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में गहरी समस्या:

- स्वास्थ्य सेवा हिंसा: रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ़ हिंसक हमलों की एक श्रृंखला से उपजा है। यह हिंसा अक्सर असंतुष्ट रोगियों और उनके परिवारों से उत्पन्न होती है, जो खराब स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भ्रष्टाचार सालाना लगभग 455 बिलियन डॉलर का नुकसान करता है, जो अन्यथा वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार कर सकता है।
- भारत में, यह भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी और सेक्सटॉर्शन सिहत विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अखंडता को और कमज़ोर करता है।
- अप्रभावी प्रतिक्रियाएँ: स्वास्थ्य सेवा हिंसा के लिए पारंपिरक प्रतिक्रियाएँ, जैसे सुरक्षा और कानूनी उपायों को बढ़ाना, अपर्याप्त साबित हुई हैं। ये घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रियाएँ हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहती हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को कानूनी सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य

- देश भर में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून मौजूद नहीं था।
- 2020 तक, 19 राज्यों ने अपने क़ानून लागू किए थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई कानून नहीं था।
- एकरूपता की कमी का मतलब है कि सुरक्षा असंगत है।
- 🔷 राज्यों में, केरल और कर्नाटक अब अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भारत में सबसे मज़बूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- केंद्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ: एक केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, और VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है।
- जबिक समवर्ती सूची एक केंद्रीय कानून की अनुमित देती है, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी है, इसे राज्यों के प्रबंधन के लिए छोड़ दिया है।

आगे की राह

- सिस्टम को मजबूत करें: इस 'खतरे' को खत्म करने के लिए, हमें जमीनी स्तर से सिस्टम को मजबूत करने के लिए अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, जैसे कि इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा अविध को कम करना।
 - o ज़रूरतमंद लोगों के लिए दवाओं, परीक्षणों और वित्तीय सहायता की उपलब्धता और पहुंच उनके तनाव को बहुत कम कर देगी, बजाय इसके कि उन्हें इसके लिए अपने चिकित्सकों को ज़िम्मेदार ठहराना पड़े।
- नीति और संस्थागत उपाय: रिश्तेदारों को हथियार ले जाने से रोकने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाना कारगर है, लेकिन वर्तमान में उन्हें निजी सेटिंग्स में लागू करना आसान है और सार्वजनिक सुविधाओं में नहीं।
 - o यह सुनिश्चित करना कि उच्च भावनात्मक संकट के समय में रोगियों और रिश्तेदारों की मदद करने के लिए परामर्शदाता हों, रोगी की स्थिति और उपचार के बारे में किसी भी गलत संचार को समाप्त कर सकता है।
 - o इसके अलावा, एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली और रोगी के बिस्तर के पास कुछ रिश्तेदारों से ज़्यादा की अनुमित न देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है।



THE De HINDU Daily News Analysis

o पश्चिम बंगाल की घटना के बाद, केंद्र सरकार ने घोषणा की

है कि वह स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अधिनियम बनाने के लिए संसद में पेश किए गए 2019 के विधेयक की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाएगी।

o जब तक कोई केंद्रीय कानून वास्तविकता नहीं बन जाता, तब तक ये राज्य स्तरीय सुधार उन लोगों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो दूसरों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

Asian Infrastructure Investment Bank

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है।

- इसकी स्थापना AIIB समझौते के लेखों (25 दिसंबर, 2015 को लागू) द्वारा की गई है, जो एक बहुपक्षीय संधि है। समझौते के पक्ष (57 संस्थापक सदस्य) बैंक के सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इसका संचालन शुरू हुआ।
- 2020 के अंत तक, AIIB के 103 स्वीकृत सदस्य थे, जो वैश्विक आबादी के लगभग 79% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 65% का प्रतिनिधित्व करते थे।



एशिया और उसके बाहर संधारणीय अवसंरचना और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके, यह लोगों, सेवाओं और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़ेगा जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।

AIIB के उद्देश्य

- अवसंरचना और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एिशया में संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, धन का सृजन करना और अवसंरचना कनेक्टिविटी में सुधार करना।
- अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास संस्थानों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करके विकास चुनौतियों का समाधान करने में क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना।
- विकास उद्देश्यों के लिए सार्वजिनक और निजी पूंजी में निवेश को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिए।
- क्षेत्र में ऐसे विकास के वित्तपोषण के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, जिसमें वे परियोजनाएँ और कार्यक्रम शामिल हैं जो क्षेत्र के सामंजस्यपूर्ण आर्थिक विकास में सबसे प्रभावी रूप से योगदान देंगे।





क्षेत्र में आर्थिक विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं, उद्यमों

और गतिविधियों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, जब निजी पूंजी उचित शर्तीं और नियमों पर उपलब्ध न हो।

AIIB के वित्तीय संसाधन

- ➡ AIIB की आरंभिक कुल पूंजी 100 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसे 100 000 डॉलर के 1 मिलियन शेयरों में विभाजित किया गया है, जिसमें 20% भुगतान किया गया है और 80% कॉल करने योग्य है।
- भुगतान की गई शेयर पूंजी: यह वह राशि है जो निवेशकों द्वारा स्टॉक के शेयरों के बदले में पहले ही चुकाई जा चुकी है।
- कॉल की गई शेयर पूंजी: कुछ कंपनियाँ निवेशकों को शेयर जारी कर सकती हैं, इस समझ के साथ कि उन्हें बाद में भुगतान किया जाएगा।
- इससे निवेश की शर्तें अधिक लचीली हो जाती हैं और निवेशकों को पहले से धन उपलब्ध कराने की तुलना में अधिक शेयर पूंजी का योगदान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- चीन बैंक में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जो आरंभिक सब्सक्राइब्ड पूंजी का आधा है। भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।

